Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 28-11-2006

Participants : Meghwal Shri Kailash

an>

Title: Need to clear pending projects under 'Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana' in Rajasthan.

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आधारभूत सुविधाएं विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्र के घरों तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अप्रेल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आरम्भ करने की घोणा की, जिसके अंतर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों का आगामी पांच वर्षों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार भी सम्मिलित हैं, को विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन जारी करना भी इसमें सम्मिलित है। इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान तथा दस प्रतिशत का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अधिकृत किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 15 योनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं, जिनसे 2,750 अविद्युतिकृत ग्रामों, 2,285 ढाणियों का विद्युतीकरण करना तथा 10,55,551 बीपीएल परिवारों और 2,17,557 सामान्य परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जिनकी स्वीकृति हेतु बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है। इनकी स्वीकृति अभी तक लम्बित है।

इन 15 योजनाओं की स्वीकृति के अभाव में राजस्थान के 15 जिलों में घरेलू कनेक्शन मय बीपीएल कनेक्शन जारी नहीं किए जा सकते, जिससे विभिन्न जिलों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान की लम्बित योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए।